

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर
3/2/07

50

न्यायालय वी०के०भा०रवानी, अपर सेशन न्यायाधीश {फा०दे०} सं-2,

अजमेर

सेशन प्रकरण संख्या 8/07 { 27/07, 24/07 }

सरकार - - अभियोगी

जनाम

डा० रजनी सिंहल पत्नी प्रमोद सिंहल जाति सिंहल निवासी रकमणी देवी मेमोरियल नर्सिंग होम, फ्राम जी चौक, नसीराबाद जिला अजमेर

- - अभियुक्ता

अपराध अन्तिर्गत धारा पी एण्ड डी टी एक्ट 94 की धारा, 23 व एम टी पी एक्ट 71 की धारा 5 तथा भा०द०स० की धारा 315 सपठित धारा 511



उपास्थात:-

1. श्री रामस्वरूप लोक अभियोजक- सरकार की ओर से ।
2. अधिवक्ता श्री के सी बीजावत -अभियुक्ता की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 22.2.08

न्यायालय द्वारा:-

उपरोक्त अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 14/11/06 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश {फा०दे०} एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्र०व० नसीराबाद के समक्ष धारा 312, 315, 316/511 भा०द०स० सपठित धारा 23 { 1 } { 3 } तथा 26 प्रस्तुत किया गया। जहाँ से प्रकरण सेशन अन्वीक्षा योग्य होने के कारण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के यहाँ उपार्पित किया गया तत्पश्चात यह प्रकरण दिनांक 27/2/07 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश {फा०दे०} संख्या-1 अजमेर को अंतरित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सामा०/2007/845 दि० 25/6/07 व श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के आदेश क्रमांक स्था०/07/546 दिनांक 29/6/07 द्वारा यह प्रकरण विधिवत निस्तारण हे। इत न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

22.2.08
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
(फास्ट ट्रक) क्र. सं. 2 अजमेर

प्रतिलिपि
क विभाग
अजमेर

तथ्य प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14/11/06 को परिवारी डा० वी०के०माधुर द्वारा एक परिवार पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्र०व० नसीराबाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्र०व० नसीराबाद द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध भा०व०स० की धारा 312, 315, 316/511 एवं धारा 23३।३३ व धारा 26 पी एण्ड डी टी एक्ट 1971 के तहत प्रस्तावित किया जाकर पत्रावली को माननीय सेशन न्यायाधीश, अजमेर के यहाँ पत्रावली को कामिट किया गया। परिवारी ने अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि परिवारी राजस्थान सरकार द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध परिवार प्रस्तुत करने को अधिकृत है अभियुक्ता पेशे से पंजीकृत चिकित्सक है जो स्कमणी देवी मेमोरियल नर्सिंग होम नसीराबाद जिला अजमेर का संचालन करती है एवं मालिक है। दिनांक 5/4/06 से 23/4/06 तक टी वी चैनल राष्ट्रीय सहारा समय में कोटा में कत्ल नामक शोषक से कार्यक्रम प्रसारित हुआ जिसमें सरकारी एवं निजी चिकित्सको एवं चिकित्सा संस्थानों के द्वारा गैर कानूनी रीति में गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग का परिक्षण करके गर्भ का समापन किया जाता है। अभियुक्ता को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अभियुक्त द्वारा गर्भपात कराने एवं जीवित बच्चे को अपरिपक अवस्था में निकालने जितने उनकी मृत्यु हो जाये इस उद्देश्य से कृत्य किया गया है। दिनांक 14/6/06 को अभियुक्ता के हास्पिटल पर जांच हेतु डा० लक्ष्मण, हरयन्दानी, अति०मु०चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, डा० रतन मंत्री वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन, डा० मधु रमा क० विशेषज्ञ, डा० जगदीशमहेश्वरी अभियुक्त के अस्पताल पहुँच कर पाया कि उक्त चिकित्सालय में से सोमोग्राफी मशीन जब्त की गयी थी जहाँ सबूत बच्चे में लिये गये। दिनांक 14/6/06 को विधिवत परिवारी द्वारा अभियुक्ता को गैर कानूनी रूप से अविधिक तौर पर गर्भ गर्भावस्था से लडकी होने पर गर्भपात की सेवास उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया तथा गर्भपात नहीं करने के निर्देश दिये गये संबंधित रेजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु निवेदन दिये गये। अभियुक्ता द्वारा कानून का उल्लंघन करके अवैध तौर आपराधिक दण्डनीय अपराध किया है परिवार सुनने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार परिवार अंदरमियाद है। अंत में निवेदन किया कि अभियुक्ता के विरुद्ध प्रस्तावित किया जाकर उन्हें दण्डित करने की कृपा करें।



का
22-2-08

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
(कॉस्ट ट्रांस) क्र सं. 2 अजमेर

सत्यपित प्रतीति

लिपिक

दिनांक 18/9/07 को अभियुक्ता को पी एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23 व एम टी पी एक्ट 1971 की धारा 5 तथा भा0द0स0 की धारा 315 तपठित धारा 511 का अलग से आरोप विरचित कर सुनाया व सम्झाया गया । अभियुक्ता ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से पी डब्लू-1 जगदीश मधेश्वरी पी डब्लू-2 लक्ष्मण हरचंदानी को पत्राक्षत कराया तथा अपनी साक्ष्य समाप्त की । तत्पश्चात अभियुक्त के कथान 313 द0प्र0स0 लेखाब्द किये गये । अभियुक्ता ने स्वयंको निर्दोश बताया तथा साक्ष्य तपगई पेश करना नहीं चाहा ।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :-
 आया दिनांक 5/4/06 को या इससे पूर्व कितनी दिन आपने महिला को गर्भापात करने के लिए व लिंग परीक्षाण के लिये सहमति दी जिसका आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था तथा अपने महिला को गर्भापात करने के लिए सहमति इस आशय की दी कि शीशु को जीवित पैदा होने से रोका जाय यदि हाँ तो इसके लिये उचित दण्ड क्या होगा 9



इस बाबत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनिदोष विवेचन इसप्रकार है कि पी डब्लू-1 डा0 जगदीशमधेश्वरी का समापथा कथन रहा है कि दिनांक 14/6/06 को उसे डा0 वी0के0माथुर द्वारा फोन करके स्कमणी देवी मेमोरियल अस्पताल मे बुलाया गया वहाँ पर डा0 लक्ष्मण हरचंदानी, डा0 मोती आसनानी डा0 वी0के0 माथुर मौजूद थे। डा0 सुत एन संत्री व डा0 मधु शर्मा को भी बुलाया गया था सब ने चिकित्सालय के सोनोग्राफी कमरे का, लेबर रूम का निरीक्षण किया । डा0 रजनी सिहल व प्रमोद सिहल को निर्देश दिया कि आगामी आदेश तक सोनोग्राफी नहीं करें। वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन तथा लेबर रूम मे संबंधित औजार थे, प्रतिपरीक्षाण के दौरान इस गवाह ने बताया है कि उसके सामने रजनी सिहल ने कितनी भी मरीज का इलाज नहीं किया न सोनोग्राफी की, न ही कितनीसेउतके सामने मरीज से कोई वार्ता हुयी उत समय कोई मरीज नहीं था।

22/2/08
 बपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 (कास्ट इंस) क्र सं. 2 अजमेर

व्यक्ति प्रतिलिपि

पी डब्लू-2 डा0 लक्ष्मण हरचंदानी ने पी डब्लू-1 के समापथा कथनों की पुष्टि की तथा प्रतिपरीक्षाण के दौरान बताया है किउतके सामने डा0 रजनी सिहल ने कितनी भी महिला की गर्भा से

केन्द्र
 विभाग
 अदालत, बखरी

संबंधित कोई जांच की ।

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण को सदिह से परे साबित करने के लिए प्रस्तुत की गयी है। विद्वान लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता दोषी करार दिये जाने योग्य है। जबकि अभियुक्ता के सुयोग्य विद्वान अभिभाषक श्री के सी बीजावत का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध को साबित करने के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभियुक्ता द्वारा किस महिला के साथ सहमति दी गयी उतका नाम तक नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषामुक्त होने योग्य हैं।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों-वितर्कों पर

गौरव किया । अभियोजन पक्ष की ओर से पी डब्लू-1 डा0 जगदीश महेवरणी

व पी डब्लू-2 डा0 ब्रह्मण हरचंदानी को परिक्षित करवाया है इन

दोनों ग्राहकों ने साक्ष्य में कहीं भी यह नहीं बताया है कि डा0 रजनी

सिंहल के द्वारा किस महिला को गर्भापात करने की सहमति दी यहाँ तक

कि उस महिला का नाम तक भी नहीं बताया है। जिसके साथ वार्ता करना

कीटात किया गया है। परिवारों द्वारा सहारा चैनल न्यूज के आधार

पर यह परिवार प्रस्तुत किया है परंतु आरोप को साबित करने के संबंध

में कोई भी सुदृढ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है यहाँ तक पी डब्लू-1 व

पी डब्लू-2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि

उसके सामने डा0 रजनी सिंहल द्वारा किसी भी मरीज का ईलाज नहीं

किया न लोनोग्राफी की , न ही वार्ता हुयी । विचारण के दौरान अभियोजन

पक्ष की ओर से सहारा स्टिंग आप्रेशन में प्रसारित न्यूज "कोखा का कत्ल "

की सी डी प्रस्तुत की गयी है जो मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि

अभियुक्त द्वारा किस महिला के साथ वार्ता की गयी तथा उसे लोनो

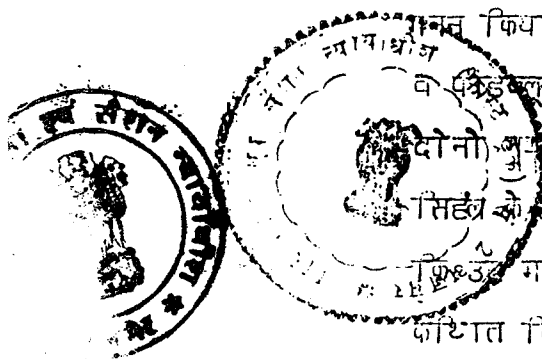
ग्राफी के लिए सहमति दी । इस प्रकार की साक्ष्य के आधार पर

अभियुक्ता को पी एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23 , एम टी पी

1971 की धारा 5 व भा0द0स0 की धारा 315 तपठित धारा 51।

के आरोप में जोड़ने में किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती हैं।

इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से



ज
बपर जिला दूधे सेगन
(कास्ट दूध) क्र सं. 2 बजमेर

प्राप्त प्रमाण

प्रमाणित
जिला
बजमेर

ते प्रकट होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने प्रकरण को सदैव ते परे
 साक्षित करने के तर्क में कोई भी सुदृढ विश्वसनीय एवं वैदिक
 साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। यहां तक कि किस महिला के साथ वार्ता की गयी
 उसका नाम भी स्पष्ट नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्ता
 दोषानुभव होने योग्य है अतः इत बिन्दु का निर्णय अभियुक्ता के
 पक्ष में एवं अभियोजन के विपरीत किया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप अभियुक्ता डा० रजनी सिंहल पत्नी प्रमोद
 सिंहल जाति सिंहल निवासी स्कमणी देवी मेमोरियल नर्सिंग होम,
 प्लम जी चौक नसीराबाद जिला अजमेर को आरोपित अपराध पी एण्ड
 डी टी एक्ट 1994 की धारा 23, एम टी पी एक्ट 1971 की धारा
 5 व भा०द०स० की धारा 315 सपठित धारा 511 में साक्ष्य के अभाव
 में दोषानुभव किया जाता है।

प्रकरणों में जब्त की गयी सोनोग्राफी रिकार्ड शैक्षणिक योग्यता एवं
 एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र व सोनोग्राफी मशीन अभियुक्ता को बाव
 गुरने दिया, अपील लौटायी जावे।

जा ११
 22-2-08

बपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 (फा०दे०) संख्या-2 अजमेर।



निर्णय आज दिनांक 22-2-08 को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय
 में प्रेषित कर तुनाया गया।

जा ११
 22-2-08

बपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 (फा०दे०) संख्या-2 अजमेर।

प्रति हस्ताक्षरित

प्रसारी अधिकारी
 केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
 न्यायालय, अजमेर
 28/2/08

प्रत्यपित प्रतिलिपि

प्रतिपिक

50

न्यायालय नम्बर...
दिनांक...
[Handwritten marks]

न्यायालय: वी०के०भारवानी, अपर तैशन न्यायाधीश फा०दे० सं०-२
अजमेर

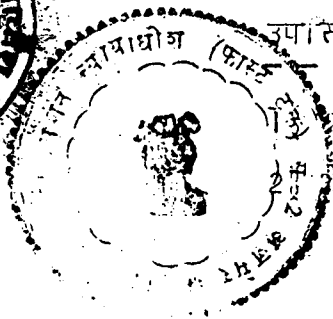
तैशन प्रकरणसंख्या 9/07 & 25/07, 26/07

तरकार - - अभियोगी
बनाम

डा०देवी पंवार निवाती प्रेमलता नर्सिंग होम, फुलम जी चौक
नतीराबाद जिला अजमेर।

- - अभियुक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा पी एण्ड डी टी एक्ट 94 की धारा
23 व एम टी पी एक्ट 71 की धारा
5 तथा भा०द०स० की धारा 315
सपठित धारा 511 ।



उपास्थात:-

श्री रामस्वस्म लोक अभियोजक-तरकार की ओर से।
श्री अधिवक्ता श्री के सी बीजावत- अभियुक्ता की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 22.2.08

न्यायालय द्वारा:-

उपरोक्त अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक
14/11/06 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश फा०दे० एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट, प्र०व० नतीराबाद के समक्ष धारा 312, 315, 316/511
भा०द०स० सपठित धारा 23 & 33 तथा 26 प्रस्तुत किया गया
जहां से मामल तैशन अन्वीक्षा योग्य होने के कारण माननीय
जिला एवं तैशन न्यायाधीश अजमेर के यहां उपाधिपित किया गया
(तत्पश्चात यह प्रकरण दिनांक 27/2/07 को न्यायालय अपर जिला
एवं तैशन न्यायाधीश फा०दे० सं०-1 अजमेर को अंतरित किया गया
माननीय उच्च न्य.यालय के आदेश सामान्य/2007/845 दि०25/6/07
व भीमान जिला एवं तैशन न्यायाधीश अजमेर के आदेश क्रमांक
स्था०/07/546 दिनांक 29/6/07 द्वारा यह प्रकरण विधावत
निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

22.2.08
अपर जिला एवं तैशन न्यायाधीश
(फास्ट ट्रक) क्र सं. 2 अजमेर

सत्यपित प्रतिलिपि

केन्द्रीय
दफ्ता एवं संलग्न न्यायालय, अजमेर

लघु प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14/11/06 को परिवार डा० वी के माधुर द्वारा एक परिवार पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, १००० नसीराबाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, १००० नसीराबाद द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध प्रा००००० की धारा 312, 315, 316/511 एवं धारा 231, 333 व धारा 26 पी एण्ड डी टी एक्ट 1971 तहत प्रसंगान लिया जाकर पत्रावली को माननीय सभान न्यायाधीश अजमेर के यहां पत्रावली को कभिट किया गया। परिवारी ने अपने परिवार पत्र में अंकित किया है कि परिवारी राजस्थान सरकार द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध परिवार प्रस्तुत करने को अधिकृत है अभियुक्ता पेशी से पंजीकृत चिकित्सक है जो प्रेमलतानर्सिस होम ग्राम्जी चौक नसीराबाद जिला अजमेर का संयोजन करती है एवं मालिक है। दिनांक 5/4/06 से 23/4/06 तक टी पी चैन्ल राष्ट्रीय सहारा समय में कोखा में कत्ल नामक शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित हुआ जिसमें सरकारी एवं निजी चिकित्सको एवं चिकित्सा संस्थानो के द्वारा गैर कानूनी रू से गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग का परीक्षण करके गर्भ का समापन किया जाता है अभियुक्ता को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अभियुक्ता द्वारा गर्भपात कराने एवं जीवित बच्चे को अपरिपक्व अवस्था में निकालने जितने उनकी मृत्यु हो जाये इस उद्देश्य से कृत्य किया गया है दिनांक 14/6/06 को अभियुक्ता के हास्पिटल पर जांच हेतु डा० लक्ष्मण हरचन्दानी, अति०मु०चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, डा० रतन मंत्री वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडितन, डा० मधु शमश क०विशेषज्ञ, डा० जगदीश महेश्वरी अभियुक्ता के अस्पताल पहुंच कर पाया कि उक्त चिकित्सालय में ना तो सोनोग्राफी मशीन है ना ही एम टी पी के लिए पंजीकृत है तथा सदस्यो की सहसम्मति से निर्णय लिया किमौके पर अवैध गर्भपात एवं जांच में प्रयोग लिये जाने वाले औजार सीज किये गये। दिनांक 14/6/06 को विधिवत परिवारी द्वारा अभियुक्ता डा० देवी पंवार को गैर कानूनी रू से अविधिक तौर पर गर्भ गर्भावस्था में लडकी होने पर गर्भपात की सेवा उपलब्ध कराते हुए अज्ञात कराया तथा गर्भपात नहीं करने के निर्देश दिये गये था। सर्वथात रजिस्टर जांच हेतु उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थे जो नोपिस दिनांक 14/6/06 को प्राप्त हो गया। अभियुक्ता द्वारा कानून का उल्लंघन करके अवैध



क/ पर जिला लेवल हेतु न्यायाधीश (फास्ट ट्रक) क्र. सं. 2 अजमेर 2008

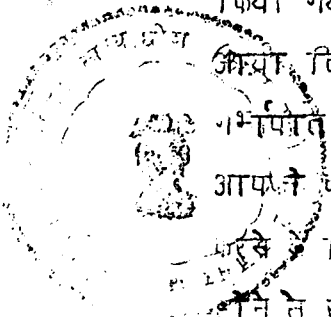
स्थायित प्रतिलिपि
 लिपिक
 क विभाग
 स्वास्थ्य विभाग, अजमेर

तौर पर आपराधिक दण्डनीय अपराध किया है परिवार सुनने का न्यायालयको क्षेत्राधिकार है। परिवार अंदरमियाद हैं। अंत में निवेदन किया कि अभियुक्ता व विरुद्ध प्रस्तावन लिया जाकर उन्हें दण्डित करने की कृपा करे ।

दिनांक 18/9/07 को अभियुक्ता को पी एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23 व एम टी पी एक्ट 1971 की धारा 5 तथा भा0द0स0 की धारा 315 तपठित धारा 511 का आरोप अलग से विरचित कर सुनाया व समझाया गया । अभियुक्ता ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से पी डब्लू-1 जगदीश महेश्वरी व पी डब्लू-2 लक्ष्मण हरचंदानी को परिक्षित कराया तथा अपनी साक्ष्य समाप्त की । तत्पश्चात अभियुक्ता के कथान धारा 313 द0पु0स0 लेखाब्द किये गये । अभियुक्ता ने स्वयं को निर्दोष बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा ।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :
अभियुक्ता दिनांक 5/4/06 को या इससे पूर्व किसी दिन आपने महिला को गर्भापात करने के लिए व लिंग परीक्षण के लिये सहमति दी जिसका आपने कोई अधिकार प्राप्त नहीं था तथा आपने महिला को गर्भापात करने के लिए सहमति इस आशय की दी कि शीशु को जीवित पैदा होने से रोका जाय यदि हां तो इसके लिये उचित दण्ड क्या होगा 9

इस बाबत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है कि पी डब्लू-1 डा० जगदीशमहेश्वरी का सशपथ कथान रहा है कि दिनांक 14/6/06 को उसे डा0 वी 0 के0माथूर द्वारा फोन करके प्रेमलता चर्चिंग होम नसीराबाद अस्पताल में बुलाया गया वहां पर डा0 लक्ष्मण हरचंदानी, डा0 मोती, आतनानी, डा0 वी0के0माथूर मौजूद थे । डा0 एन एन मंत्री व डा0 मधु शर्मा को भी बुलाया गया था तब नै चिकित्सालय के सोनोग्राफी कमरे का , लेबर रूम का निरीक्षण किया । डा0 देवी चंवार को निर्देश दिया कि आगामी आदेश तक सोनोग्राफी नहीं करें। अस्पताल एम टी पी के लिये पंजीकृत नहीं है। उनके पास जो भी सामान एम टी पी में काम आने वाला था सील कर दिया गया। प्रतिपरीक्षा के दौरान अन्वेषक ने बताया है कि उसके सामने डा0 देवी चंवार ने कभी भी मरीज काईला नहीं किया न सोनोग्राफी की , न ही किसी से उने अपने मरीज से कोई बातें हूयी उस समय कोई मरीज नहीं था।



22.2.08
अपर जिला न्याय सेशन न्यायाधीश
(कास्ट ट्रान्) क्र सं. 2 अजमेर

अस्वीकृत प्रतिनिधि

केन्द्र
न्याय सेशन न्यायालय, अजमेर

पी डब्लू-2-डा0 लक्ष्मण हरचंदानी ने पी डब्लू-1 के सभापथ कथानों की पुष्टि की तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान बताया है कि उसके सामने डा0 देवी पंवार ने किसी भी महिला की गर्भा से संबंधित कोई जांच की।

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण को सिद्ध से परे साबित करने के लिए प्रस्तुत की गयी है। विद्वान लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता दोषी करार दिये जाने योग्य है। जबकि अभियुक्ता के सुयोग्य विद्वानअभिभाषक श्री के सी बीजावत का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध को साबित करने के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभियुक्ता द्वारा किस महिला के साथ सहमति दी गयी उसका नाम तक नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्ता दोषमुक्त होने योग्य है।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों-वितर्कों पर मनन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पी डब्लू-1 डा0 जगदीश महेश्वरी व

पी डब्लू-2 डा0 लक्ष्मण हरचंदानी को परिद्वेषित करवाया है इन दोनों ने साक्ष्य में कहीं भी यह नहीं बताया है कि डा0 देवी पंवार के द्वारा किस महिला को गर्भापात करने की सहमति दी यहाँ तक कि उस महिला का नाम तक भी नहीं बताया है। जिसके साथ वातावरण करना धरित किया गया है। परिवादी द्वारा सहारा चैनल न्यूज के आधार पर यह पारिवाद प्रस्तुत किया गया है परंतु आरोप को साबित करने के संबंध में

कोई भी सुदृढ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है यहाँ तक पी डब्लू-1 व

पी डब्लू-2 ने अपने प्रतिपरीक्षाके दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके सामने डा0 देवीपंवार द्वारा किसी भी मरीज काईलाज नहीं किया न सोनोग्राफी की, न ही पार्ता हुयी। दिवारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहारा स्टिंगअप्रेसान में प्रसारित न्यूज कोटा का कत्ल की सी डी प्रस्तुत की गयी है जो मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए है।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्ता द्वारा किस महिला के साथ वाता की गयी तथा उसे सोनोग्राफी के लिये सहमति दी। इस प्रकार की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता को पी एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23, एम टी पी 1971 की धारा 5 व भा0 दोस0की धारा 315 तपठित धारा 511 के आरोप में जोडने में किसी प्रकार की कोई मजद नहीं मिलती है।



22.2.08
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
(कास्ट ट्रा) क. सं. 2 काजमेर

सत्यपिप्त प्रतिनिधि

केस
क विभाग
सत्य, सचपीर

मिठा

इस प्रकार तादय के उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से प्रकट होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने प्रकरण को लट्टि से परे लापित करने के लक्ष्य में कोर्ट भी तुष्ट, विश्वसनीय एवं वैदिक तादय प्रस्तुत नहीं की है। यहाँ तक कि फिर महिला के साथ वार्ता की गयी उसका नाम भी स्पष्ट नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्ता दोषामुक्त होने योग्य है अतः इस बिन्दु का निष्पत्त अभियुक्ता के पक्ष में एवं अभियोजन के विपरीत किया जाता है।

आदेश

पारणामत्वस्व अभियुक्ता डा० देवी पंवार निवासी प्रेमलता नर्तन होम फ्राम जी चौक नसीराबाद जिला अजमेर को आरोपित अपराध की एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23, एम टी पी एक्ट 1971 की धारा 5 व भा०द०स० की धारा 315 समित धारा 511 से तादय के अभाव में दोषामुक्त किया जाता है।

प्रकरण ने जब्त एक रजिस्टर व औजार कब्जे में लिये गये जो सीज है बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार अभियुक्ता को लौटाये जाय।

22.2.08

वी०के० भारवानी
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
(कास्ट टुक) फ. सं. 2 अजमेर
संख्या-2 अजमेर।



आज दिनांक 22.2.08 को मेरे द्वारा विवृत न्ययलय में सुनाया गया।

22.2.08

वी०के० भारवानी
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
(कास्ट टुक) फ. सं. 2 अजमेर
संख्या-2, अजमेर।

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभारी न्यायाधीश
केन्द्रीय प्रतिलिपि कार्यालय
हिंदा संशु न्यायालय, अजमेर

28/2/08

प्रतिलिपि

केन्द्रीय प्रतिलिपि कार्यालय
हिंदा संशु न्यायालय, अजमेर



कार्यालय टिपणी/क्रमिक टिपणी

विषय :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर से प्राप्त सरकार बनाम डॉ० देवी पर्वार एवं सरकार बनाम रजनी सिंघल में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विवरण निम्न प्रकार है :-

- प्रकरण सैशन प्रकरण 9/07 सरकार बनाम डॉ० देवी पर्वार एवं 8/07 सरकार बनाम डॉ० रजनी सिंघल में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पताका ए से संबंधित है।
- जिसमें डॉ० वी०के०माथुर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिनांक 14.11.06 को आरोपी चिकित्सको के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नसीराबाद के यहाँ परिवाद पेश किये।
- न्यायालय न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नसीराबाद द्वारा धारा 312,315,316/511 भा.द.स., धारा 23 (1)(3) एवं धारा 26 पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के तहत प्रसंज्ञान लिया गया।
- सैशन अन्वीक्षा होने के कारण इसका विचारण अपर सैशन न्यायाधीक्ष (फास्ट ट्रैक संख्या 2) द्वारा किया गया।
- दिनांक 18.09.2007 को दोनो अभियुक्ताओं के विरुद्ध धारा 23 पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994, धारा 5 एमटीपी एक्ट, 1971 एवं धारा 315/511 के तहत आरोप माननीय न्यायालय द्वारा तय किये गये।
- अभियोजन पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय द्वारा जगदीश माहेश्वरी एवं लक्ष्मण हरचन्दानी को परीक्षित किया गया।
- दिनांक 22.02.08 को माननीय न्यायालय, अपर जिला एवं सैशन न्यायालय (फास्ट ट्रैक) संख्या 2, अजमेर द्वारा डॉ० रजनी सिंघल एवं डॉ० देवी पर्वार को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है।

माननीय न्यायालय, अपर जिला एवं सैशन न्यायालय (फास्ट ट्रैक) संख्या 2, अजमेर के उक्त निर्णय की अपील किये जाने के संबंध में विचारणीय बिन्दु जिन पर विधि विभाग की राय लिया जाना प्रस्तावित है।

- माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना गया कि प्रकरण सहारा समय न्यूज चैनल पर दिखाये गये कोख में कत्ल से संबंधित है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा उस महिला जिसके साथ आरोपी चिकित्सको द्वारा बातचीत की गई का विवरण नाम सहित उपलब्ध नहीं करवाने का हवाला दिया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकारों एवं अन्य गवाहों की सूची भी माननीय न्यायालय को उपलब्ध कराई गई थी जिनको कि विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षित नहीं किया गया जो कि उक्त प्रकरण के अहम गवाह थे।

पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

DM
21/06/08
LA-PCPNDT

अति० निदेशक (प०क०)

DM
21/6/08

निदेशक (प०क०)

DM
25/6/08

DM

→

PCPNDT cell/09/37
21/06/08 2

सि.सं. 1490

3

2008

3

अपर सेशन न्यायधीश (फास्ट ट्रैक) अजमेर के निर्णय दिनांक 22.02.08 के द्वारा अभियुक्ता डॉ. रजनी सिंहल को पी.सी. पी. एण्ड डी.टी.एक्ट 1994 धारा 23 एवं एम्पी. एक्ट की धारा 5 एवं आई.पी.सी. के प्रावधानों के तहत साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया ।

4

न्यायालय ने विभाग के साक्ष्य लक्ष्मण हरचंदानी एवं जगदीश माहेश्वरी के बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को अपर्याप्त माना जबकि यह साक्ष्य तो स्टिंग आपरेशन के पश्चात् उनके द्वारा अभियुक्त के क्लिनिक की जाँच से संबंधित थे । मूल अपराध को सहारा सी.डी. में अंकित तथ्यों के आधार पर बनता है । निर्णय में सी.डी. प्रस्तुत करने का उल्लेख आया है किन्तु इसकी मूल सी.डी. प्रस्तुत नहीं की है । अतः न्यायालय को मूल सी.डी. एवं उसमें अंकित गवाहों जिसकी सूची अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी थी को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस देकर बुलाया जाना चाहिए । सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आवश्यक संबंधित गवाह सूची एवं मूल सी.डी. हेतु गवाहों को नहीं बुलाकर त्रुटी की है । अतः इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जानी चाहिये ।

Rajni D. Singh
Dated... 30/6/08

उप विधि परामर्शी

लिखित / 430
30/6/08

निदेशक (प.क.)
1 JUL 2008

Address

8/7/08

Ritehoiwai

उप विधि परामर्शी, निदेशालय की राय पैरा 3/N के पश्चात् पैरा 1/N व 2/N का अवलोकन करने का कष्ट करें जिले के अनुसार उक्त प्रमाण में अपील करने लिए जाने की अपेक्षा आगामी रायबारी के रूप में पर्यावली विधि विभाग निजवासा धारा प्रस्तावित है

344/PMS/2008
4.7.2008

अतः पर्यावली अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है

03/07/08

अ.व. दि. (RCM)

8/7/08

दि. (RCM)

9/7/08

2008

PMS

पु.सा.वि. विधि विभाग

8/7
PL

Handwritten signature

ACR

258/1/2008
8/7

1409/DC/08
8/7/08

2112/6-4/08

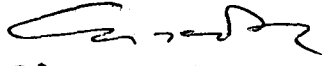
विषय: - सेशन प्रकरण सं. 09/2007, 25/2007, 26/2007।
सरकार बनाम डा. देवी परिवार, न्यायालय अमर
सेशन न्यायाधीश: फास्टट्रेक। सं. 2, अजमेर
धारा पी. एण्ड डी. टी. एक्ट, 94बी धारा 23 व
एम. टी. पी. एक्ट. 71 की धारा-5 भा. द. सं. की
धारा 315 तय्यत धारा 511.

सन्दर्भ: - आपकी पत्रावली क्रमांक 3344/पीएसएस/2008
दिनांक 4-8/7/2008

DLB
3

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण के सम्बन्ध में लेख है कि प्रकरण जिला
क्लक्टर, अजमेर से इस विभाग को अपील के प्रस्ताव के साथ प्राप्त नहीं हुआ
है तथा जिला क्लक्टर को प्रकरण में आगे अपील नहीं करने का विनिश्चय
लेने का अधिकार है।

यदि विभाग में प्रकरण में अपील चाहता है तो इस सम्बन्ध में
जिला क्लक्टर, अजमेर से पत्राचार कर अनुरोध करें।


निदेशक, राजकीय वादकरण

प्रमुख शासन सचिव,
चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग

अ. शा. टीप सं. म. 3/216/विधि-4/2008

जयपुर, दिनांक 18/8/08

प्रतिलिपि जिला क्लक्टर, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक, राजकीय वादकरण

12/16-41-8
18/8/08 572 572/काका

3344/HS/2008
19/8-08

11/11/08
27/8/08



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी०सी०पी०एन०डी०टी० सैल
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी सैल /2008/ 114

दिनांक : 3/9/08

जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
जिला कलेक्टर, अजमेर

विषय :- सैशन प्रकरण संख्या 9/07 सरकार बनाम डॉ० देवी पर्वार एवं 8/07 सरकार बनाम डॉ० रजनी सिंघल में न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक-2) के दिनांक 22.02.08 के निर्णय की अपील के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त सैशन प्रकरण में अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक-2) द्वारा दिनांक 22.02.08 को दिये गये निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निदेशालय को भिजवाई गई थी। उक्त दोनो सैशन प्रकरण सहारा समय न्यूज चैनल द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के उल्लंघन के संबंध में किये गये स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है। इन मामलो में माननीय न्यायालय द्वारा स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित गवाहो का परीक्षण नहीं किया गया है जो कि प्रकरण में अहम गवाह थे।

उक्त निर्णय के संदर्भ में अपील हेतु पत्रावली विधि विभाग को भिजवाई गई थी, जिस पर निदेशक, राजकीय वादकरण से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ कि उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर, अजमेर से विभाग को अपील हेतु कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और यदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विभाग इन प्रकरणों में अपील चाहता है तो जिला कलेक्टर अजमेर से पत्राचार कर अनुरोध करें (पत्र की प्रति संलग्न है)

अतः निवेदन है कि सैशन प्रकरण संख्या 9/07 सरकार बनाम डॉ० देवी पर्वार एवं 8/07 सरकार बनाम डॉ० रजनी सिंघल में न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक-2) के दिनांक 22.02.08 के निर्णय की अपील के संबंध में आप द्वारा लिये गये निर्णय से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
निदेशक (पी०क०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
2. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
निदेशक (पी०क०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक: कअ/विधि/अपील/2008/575 दिनांक 22.09.2008

निमित्त :- अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
निदेशक प.क. १
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज० जयपुर ।

विषय :- सै. प्र. सं. 9/07 सरकार बनाम डॉ. देवी पंवार एवं
8/07 सरकार बनाम डॉ. रजनी सिंघल में न्यायालय
अपर सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक-2 अजमेर के निर्णय
दिनांक 22.2.2008 के विरुद्ध अपील के संबंध में ।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक: राज्य पी. सीपीएनडीटी सैल/
2008/114 दिनांक 3.9.2008

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरणों में अभियोजन की ओर से साक्षी
नहीं होने से आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है । माननीय अपर जिला
एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक-2 अजमेर के निर्णय दिनांक 22.2.2008 के
विरुद्ध लोक अभियोजक, अजमेर की राय के अनुसार एवं इस कार्यालय द्वारा
अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है । फिर भी प्राप्त लोक अभियोजक
अजमेर की राय एवं माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.2.2008 की
प्रति आपको विभाग स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रासंगिक पत्र के
क्रम में प्रेषित है ।

संलग्न:- 1. निर्णय की प्रति
2. लोक अभियोजक, अजमेर
की राय की प्रति ।

भवदीय

जिला मजिस्ट्रेट

अजमेर

रामरवरूप
एडवोकेट

लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक
राजस्थान उच्च न्यायालय



कार्यालय:
रेल्वे पावर हाउस के सामने
नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर
☎0145-2620617, (मो.) 9829436617

क्रमांक 297

दिनांक 12.03.08

TO,

श्रीमान् जिला कलेक्टर, न्याय शाखा
अ ज मे र ।

विषय :- सैन प्रकरण सं. 9/07 सरकार बनाम डा. देवी पंवार,
सैन प्र. सं. 8/07 सरकार बनाम डा. रजनी सिंघल,
उपरोक्त मुकदमों में दिनांक: 22.02.08 को
अपर जिला एवं सैन न्यायाधीश (फास्ट्रेक) सं. 2,
अजमेर, श्री वी. के. भारवानी द्वारा पी एण्ड डी. टी.
एक्ट 1994 की धारा 23 व एम. टी. पी. एक्ट
1971 की धारा 5 तथा धारा 315/511 भा. दं.
सं. के अन्तर्गत पारित निर्णय में न्यायालय द्वारा
डा. रजनी सिंघल एवं डा. देवी पंवार को अपराध
के आरोपों से बरी किये जाने के सम्बंध में चाही
गई राय बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त मुकदमों में परिवारवादी
डा. वी. के. माधुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा
दिनांक: 14.11.06 को एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि
दिनांक: 05.04.06 से 23.04.06 तक टी. वी. चैनल राष्ट्रीय सहारा
में "कोई मे कत्ल" नामक शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित हुआ जिसमें
सरकारी व निजी छल चिकित्सकों एवं चिकित्सा संस्थान द्वारा अवैध
व गैर कानूनी रूप से कानून का उल्लंघन करते हुए गर्भधारण पूर्व प्रसवपूर्व
लिंग का परीक्षण कर गर्भ का समापन किया जाता है और कानून का
उल्लंघन किया जाता है जिसके अनुसार अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से

लगातार पेज-2 पर

1113
18-3-08

रामरवरूप
एडवोकेट

गर्भगत किया गया, जबकि अभियुक्तगण को गर्भगत कराने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था, आदि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा उक्त परिवाद में डा० रजनी सिंघल स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं डा० देवी बंवार के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय द्वारा उक्त मुकद्दमे को नती धारा 156(3) द. प्र. सं. के तहत पुलिस में जांच हेतु भेजा गया और ना ही परिवादी के बयान हुए हैं तथा यह मुकद्दमा सिविल न्यायाधीशों क. ड. नसीराबाद, के समक्ष पेश किया गया तथा न्यायालय द्वारा भी बिना बयान लिये, बिना पुलिस की रिपोर्ट लिये मामले को कैमल सुर्द कर दिया गया तथा कैमल सुर्द जब किया गया उसमें अभियोजन को जो साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी उसमें केवल मात्र पी. ड. 1 जगदीश माहेश्वरी, पी. ड. 2 लक्ष्मण हरचंदानी को पेश किया गया जिन्होंने अपनी साक्ष्य में केवल यह बयान दिया है कि जांच के दौरान अस्पताल में सोनोग्राफी की मशीन नहीं मिली तथा अस्पताल एम. डी. पी. के लिए पंजीबद्ध नहीं है, उनके पास जो भी सामान था वह एम. टी. पी. में काम में आने वाला सामान सील कर दिया गया। दोनों बवाहन की साक्ष्य इसी बाबत थी।

उपरोक्त अभियोजन के बवाहन के बयानों से उपरोक्त प्रकरणों में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी अपराध साबित नहीं होता है तथा इस बात को कहने में कोई भी शंका नहीं है कि स्वयं परिवादी से भी कोई अपराध बनना नहीं पायाजाता है।


वास्तव में होना यह चाहिए था कि जिस प्रकार से जयपुर में अशोक नगर थाने में मुकद्दमा दर्ज किया गया उसी प्रकार अजमेर में उक्त मुकद्दमा दर्ज होने चाहिए थे तथा इसकी पुलिस जांच करती, सम्बंधित सामान को कब्जे में लेती उसे सील करती, हिडेन कंमरा के व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय सहारा बैंक पर कार्य कर रहे थे उसके बयान लेती, एवं साथ ही उन व्यक्तियों

से भी पृष्ठताप करती जिन्होंने गर्भा अवस्था में कन्याभ्रूण होने के बाबत बातचीत की एवं कन्या भ्रूण को ब समाप्त कराने के लिए सम्बंधित चिकित्सकों/अभियुक्तगणों ने क्या सलाह दी, आदि ध्यान लेकर एवं सम्बंधित साक्ष्य को इकट्ठित करके नियमानुसार अभियुक्तगण की गिरफ्तारी बनायी जाती तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने पर सम्बंधित अभियुक्तगण से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इस्तला लेती एवं सम्बंधित किन-किन महिलाओं के गर्भ से कन्या भ्रूण हटाया गया, की सम्पूर्ण जाँच करती तो उस परिस्थिति में उपरोक्त अपराध साबित किया जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में शुरू से ही उपरोक्त प्रकरणों में जान बूझकर लापरवाही बरती गई। यदि समय रहते हुए सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विधिक राय लेकर याद कार्यवाही करते तो निश्चित रूप से अभियुक्तगण के विरुद्ध तक्षम ~~उपरोक्त~~ कार्यवाही होती एवं कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें दण्डित कराया जा सकता था।

अतः वर्तमान प्रकरणों में अपील करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके द्वारा चाही गई राय नियमानुसार प्रेषित है।

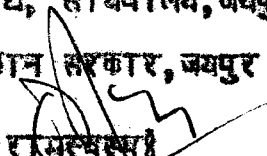
अजमेर।

दिनांक: 12.03.08


 [रामस्वामी]
 राज्यीय अभियोजक, अजमेर।

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
- 2] श्रीमान् विशिष्ट शासन अचिव विधि, सचिवालय, जयपुर।
- 3] श्रीमान् निदेशक अभियोजन, राजस्थान सरकार, जयपुर।


 [रामस्वामी]
 लोक अभियोजक एवं राज्यीय अभियोजक
 अ. म. से. वि. वि.
 राजस्थान सरकार